क्या म्यांमार में फिर से लोकतंत्र लौट आएगा?

श्रीपति नारायणन, पीएच.डी.

म्यांमार ने 1 फरवरी, 2021 को सेना द्वारा तख्तापलट करने के बाद अपने अध्यक्ष, सीनियर जनरल मिन आंग हलांग के संरक्षण में राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) के रूप में सैन्य नेतृत्व वाली (तातमाडॉ) सरकार का दूसरा वर्ष पूर्ण किया। सैन्य अधिग्रहण के बाद से, राष्ट्र, विशेष रूप से सैन्य प्रशासन, को प्रतिरोध की अधिकता का सामना करना पड़ा है जो जातीय सशस्त्र समूहों (ईएजी) और लोकतंत्र समर्थक नागरिक प्रतिरोध दोनों के बीच है। जिन नागरिकों ने हथियार उठाए हैं, अधिकतर पीपुल्स डिफेंस फोर्स (पीडीएफ) के बैनर तले, जिसे निर्वासन में सरकार के विस्तार के रूप में देखा जाता है-राष्ट्रीय एकता सरकार (एनयूजी), सैन्य अधिग्रहण को चुनौती देने के लिए, बड़े पैमाने पर बामर जातीयता से हैं।

4 जनवरी को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए जनरल मिन आंग हलांग ने कहा कि राष्ट्र "वास्तविक, अनुशासन-समृद्ध बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली" के रूप में लोकतांत्रिक दायरे में वापस आ जाएगा[1]। एसएसी के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि, जब राष्ट्र में चुनाव होंगे, तो 2008 के संविधान के अनुसार होंगे, और "राज्य कर्तव्यों" को "लोकतांत्रिक मानकों के अनुसार जीतने वाली पार्टी को" सौंप दिया जाएगा[2]।

कुछ मायनों में यह आशा की जा रही है कि देश अगस्त में चुनाव करवा रहा है[3]। हालांकि, चुनावी कवायद की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाए गए हैं। चिंता का विषय यह है कि एसएसी ने उन नियमों और विनियमों को पुन: परिभाषित किया जिनके तहत प्रस्तावित चुनाव होने हैं। यह अपने आप में एनयूजी के लिए एक बाधा साबित हो सकती है, जिसने पहले ही कहा है कि चुनाव एक 'दिखावटी'[4] राजनीतिक कवायद होगी। जबकि चिन डिफेंस फोर्स जैसे ईएजी ने पहले ही कहा है कि वे "आतंकवादी सैन्य परिषद को चुनाव नहीं करने देंगे, जो निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है[5]। वर्तमान प्रशासन ने भी अपनी ओर से चुनाव कराने के संबंध में चिंता व्यक्त की है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि एसएसी का आरोप है कि सशस्त्र प्रतिरोध के परिणामस्वरूप मतदाता डेटा एकत्र करने में व्यवधान हुआ है[6]।

इस बीच, तख्तापलट की दूसरी वर्षगांठ पर एसएसी ने तीसरी बार आपातकाल की स्थिति को बढ़ा दिया है, जबकि साथ ही यह भी कहा कि चुनाव योजना के अनुसार होंगे। बहरहाल, इस घटनाक्रम का चुनाव पर असर पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

हालांकि, तर्कसंगत को समझने के लिए कि सेना ने 2023 में चुनाव कराने की प्रतिबद्धता क्यों जताई। 2008 के संविधान के मौलिक चरित्र को समझना महत्वपूर्ण है, जिसे बाद के खंडों में विस्तार से बताया गया है।

म्यांमार और सैन्य प्रशासन की इसकी विरासत

वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलांग के नेतृत्व में एसएसी का गठन कुल मिलाकर म्यांमार की पिछली प्रथाओं के अनुरूप है। एक राष्ट्र जो 1962 से किसी न किसी रूप में सैन्य शासन के अधीन रहा है, उसने बार-बार जनरलों और सैन्य नेतृत्व वाले प्रशासनों को देखा है। राज्य कानून और व्यवस्था बहाली परिषद (एसएलओआरसी) और राज्य शांति और विकास परिषद (एसपीडीसी) हैं जिन्होंने 1988 और 2011 के बीच देश को प्रशासित किया था।

एसएलओआरसी और इसके उत्तराधिकारी एसपीडीसी 1980 के दशक की राजनीतिक अशांति के उत्पाद थे, विशेष रूप से 8 अगस्त, 1988 के सार्वजनिक विरोध और 1990 की चुनावी राजनीति के साथ बाद का प्रयोग, जिसे प्राय: पर 8888 के विद्रोह के रूप में जाना जाता है[7],। एसएलओआरसी की निगरानी में 1990 का चुनाव नागरिक शासन की वापसी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नहीं था, बल्कि राज्य के मामलों में उनके प्रभाव से समझौता किए बिना लोकप्रिय आकांक्षाओं को तुष्ट करने के लिए सशस्त्र बलों का एक प्रयास था। हालांकि आंग सान सू ची के नेतृत्व में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) की शानदार जीत ने पासा पलट दिया। सशस्त्र बल न केवल एनएलडी की एकतरफा चुनावी जीत के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र और एक लोकतांत्रिक केंद्र के उदय से भी आशंकित थे। उस चरण में चुनाव को दरकिनार कर दिया गया और सैन्य प्रशासन जारी रहा।

लोकतंत्र के साथ प्रयोग

1990 के दशक के उत्तरार्ध में सैन्य प्रशासन, तातमाडॉ, एक अनुपालन नागरिक सरकार के दृष्टिकोण के आसपास आया था। इसे महसूस करते हुए तातमाडॉ ने 2003 में "अनुशासित लोकतंत्र के लिए सात कदम रोड मैप" का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य जनरलों की याचिका को त्यागे बिना प्रशासन के बोझ को नाममात्र नागरिक प्रतिष्ठान को आउटसोर्स करना था। इसी सिद्धांत में 2008 का संविधान प्रख्यापित किया गया था और उसी संविधान के नाम से 2010 में देश में चुनाव हुए थे।

सेना प्रायोजित राजनीतिक दल यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (यूएसडीपी) को 2010 के चुनावों में जीत दिलाने के लिए एसपीडीसी प्रशासन ने आंग सान सू ची की नजरबंदी बढ़ा दी थी। यह ऐसी परिस्थिति में था कि पूर्व जनरल थेन सीन ने यूएसडीपी के समर्थन से मार्च 2011 में राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। बहरहाल, जब तक देश 2015 के चुनावों की ओर बढ़ा, तब तक तातमाडॉ को लोकतंत्र के आदी के रूप में देखा जाने लगा। यह स्पष्ट था क्योंकि एनएलडी ने न केवल चुनाव लड़ा था, बल्कि चुनाव भी जीता था। हालांकि, दशकों के सैन्य शासन के बाद 2021 में एक बार फिर से एक वास्तविक नागरिक सरकार की वापसी नहीं थी जो तातमाडॉ के लिए चिंता का विषय था। इसके विपरीत, यह एनएलडी था जिसने 2020 के चुनावों में खुद को पछाड़ दिया था, जिसने फिर से एक समानांतर/प्रतिद्वंद्वी सत्ता केंद्र की आशंका पैदा कर दी थी, जिसके परिणामस्वरूप सैन्य तख्तापलट हुआ था। जनरल मिन आंग हलांग द्वारा चुनावी कदाचार के आरोप, तख्तापलट का पूर्वाभास थे।

तख्तापलट के दो वर्ष

तख्तापलट करने के बाद जनरल मिन आंग हलांग ने वादा किया था कि देश में एक वर्ष में चुनाव हो जाएंगे के भीतर चुनावी मैदान में लौट आएगा। अगस्त 2023 में भी इस वादे को पूरा करने की अपनी शर्तें होंगी।

पहला होगा मौजूदा सुरक्षा माहौल। फरवरी 2021 के तख्तापलट से पहले भी, जिसमें एसएलओआरसी और एसपीडीसी के कार्यकाल के दौरान तातमाडॉ और ईएजी के बीच हुए संघर्ष विराम समझौतों में काफी दरार देखी गई थी, जिसके बाद पिछली एनएलडी सरकार की 21वीं सदी के पांगलोंग पहल के बाद केंद्रीय शांति सम्मेलन- 21वीं शताब्दी की पैंगलॉन्ग पहल हुई थी। तख्तापलट ने न केवल देश में कुछ ईएजी और तातमाडॉ के बीच संघर्ष को बढ़ा दिया है, बल्कि कुछ ईएजी के लिए पीडीएफ स्वयंसेवकों को हथियारों में कॉमरेड के रूप में स्वागत करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है।

दूसरा, पिछले दशक के लोकतंत्र की झलक के साथ-साथ दूरसंचार में वृद्धि के परिणामस्वरूप लोगों के रवैये में काफी बदलाव आया है। बाहरी दुनिया के संपर्क में आने के साथ, म्यांमार के लोग, विशेष रूप से बामर जातीयता के बीच, अब एक 'बहुलवादी लोकतांत्रिक' सरकार की आकांक्षा रखते हैं। यह लोगों के दृष्टिकोण में यह परिवर्तन है जो एसएसी के विरूद्ध पीडीएफ के सशस्त्र प्रतिरोध को उत्तेजित कर रहा है।

तीसरा, ईएजी के बीच आंतरिक गतिशीलता में भी काफी परिवर्तन आया है। यह उस प्रभुत्व/प्रमुखता में सबसे अधिक दिखाई देता है जो कुछ नए ईएजी पुराने ईएजी की कीमत पर हासिल करने के लिए आए हैं। इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान सशस्त्र संघर्ष की गतिशीलता में बदलाव आया है। इसके कारण, एसएसी ने दिसंबर 2022 के अंत में कुछ ईएजी के साथ संघर्ष विराम समझौते को 2023 के अंत तक बढ़ा दिया[8]। हालांकि, संघर्ष विराम व्यवस्था का विस्तार करने का स्वागत किया जा सकता है, लेकिन पिछले एक वर्ष में थाईलैंड, बांग्लादेश और भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में तातमाडॉ के सशस्त्र अभियानों का भी विस्तार हुआ है।

चौथा, चिंता का विषय यह होगा कि तातमाडॉ ने पूर्व सरकार के प्रमुख सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार किया है। गौरतलब है कि म्यांमार में लोकतांत्रिक आंदोलन का चेहरा रहीं 77 वर्षीय आंग सान सू ची को विभिन्न आरोपों में 33 वर्ष जेल की सजा काटनी है। यह एक बाधा के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह किसी भी सार्थक राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सीमित करेगा और एनएलडी/एनयूजी को रचनात्मक तरीके से तातमाडॉ के साथ जुड़ने से हतोत्साहित करेगा। इससे स्वतंत्र, ऐसी आशंकाएं हैं कि संशोधित चुनाव कानूनों का उपयोग एसएसी द्वारा एनएलडी/एनयूजी को गैरकानूनी घोषित करने या आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध रखने पर रोक लगाने के लिए किया जा सकता है[9]।

पांचवां मुद्दा दक्षिण पूर्व एशियाई देश संगठन (आसियान) के सामान्य स्थिति की वापसी के लिए 'पांच सूत्री सहमति' के प्रति एसएसी की सीमित ग्रहणशीलता है। यह न केवल एक तटस्थ पक्ष द्वारा शांति निर्माण के प्रयासों को सीमित करता है, बल्कि म्यांमार के बाहरी जुड़ाव को भी सीमित करता है। ऐसा इसलिए है,

क्योंकि राष्ट्र को न केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कुछ वर्गों से प्रतिबंधों के अधीन किया गया है, बल्कि आसियान ने इस राष्ट्र के साथ अपने जुड़ाव को गैर-राजनीतिक स्तर तक सीमित कर दिया है।

आगे क्या?

यदि अतीत कोई मार्गदर्शक है, तो यह काफी संभव है कि तातमाडॉ प्रशासन पर अपनी बागडोर नहीं छोड़ेगा। चुनाव का वादा केवल मौजूदा प्रशासन को वैध बनाने का एक साधन बन सकता है। यह दो कारणों से है। पहला तथ्य यह है कि जब भी चुनाव होंगे, 2008 के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होंगे। संविधान के प्रावधानों के अनुसार, एक चौथाई प्रतिनिधियों की नियुक्ति सैन्य प्रमुख जनरल मिन आंग हलांग द्वारा की जानी है। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब यह होगा कि एक राजनीतिक दल जो तातमाडॉ के साथ गठबंधन करता है, उसे संघीय सरकार बनाने के लिए केवल संसदीय सीटों का एक और चौथाई सुरक्षित करने की आवश्यकता होगी।

दूसरा, केंद्रीय चुनाव आयोग (यूईसी) ने कहा है कि अगले चुनाव वर्तमान फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम के बजाय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में होंगे[10]। यह बदले में अन्य छोटे राजनीतिक दलों को सुविधा प्रदान करेगा, जिनमें पिछले दो चुनावों की तुलना में संघीय संसद में अधिक सीटों के साथ सेना के साथ गठबंधन शामिल हैं। इसका मतलब यह भी होगा कि तातमाडॉ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, राज्य के मामलों में अधिक अधिकार के साथ आएगा।

अंत में, जारी आंतरिक संघर्षों के संबंध में, यह संभव है कि तातमाडॉ व्यक्तिगत ईएजी के साथ संलग्न होगा और उन्हें संघर्ष विराम व्यवस्था करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। यह एक समान दृष्टिकोण था जो 1990 के दशक में एसएलओआरसी और एसपीडीसी द्वारा लोकतंत्र के लिए अपना रोड मैप पेश करने से पहले लिया गया था।

पाद-टिप्पणियां

[1] ग्रांट पेक, "म्यांमार सेना के नेता ने स्वतंत्रता दिवस पर चुनाव योजना बनाई", *एसोसिएट प्रेस,* 4 जनवरी, 2023, https://apnews.com/article/politics-myanmar-united-kingdom-min-aung-hlaing-san-suu-kyi-e4494652527c2e9c7ef5900a6c521d44, 17 जनवरी, 2023 को अभिगम्य।

[1] ग्रांट पेक, "म्यांमार सेना के नेता ने स्वतंत्रता दिवस पर चुनाव योजना बनाई", *एसोसिएट प्रेस,* 4 जनवरी, 2023, https://apnews.com/article/politics-myanmar-united-kingdom-min-aung-hlaing-san-suu-kyi-e4494652527c2e9c7ef5900a6c521d44, 17 जनवरी, 2023 को अभिगम्य।

[3] ग्रांट पेक, "म्यांमार सेना के नेता ने स्वतंत्रता दिवस पर चुनाव योजना बनाई", *एसोसिएट प्रेस*, 4 जनवरी, 2023, https://apnews.com/article/politics-myanmar-united-kingdom-min-aung-hlaing-san-suu-kyi-e4494652527c2e9c7ef5900a6c521d44, 17 जनवरी, 2023 को अभिगम्य।

[4] खिन लिन क्याव, "म्यांमार जुंटा ने राजनीतिक दलों के लिए कठिन नियमों के साथ चुनाव की योजना बनाई", *ब्लूमबर्ग,* 27 जनवरी, 2023, https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-26/myanmar-election-junta-plans-poll-with-strict-rules-for-political-parties?leadSource=uverify%20wall, 30 जनवरी, 2023 को अभिगम्य।

[5] हेन हतू ज़ान, "म्यांमार शासन ने नियोजित चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को संकलित करना शुरू किया", *इरावडी*, 11 जनवरी, 2023, https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-regime-begins-compiling-voter-lists-for-planned-election.html, 31 जनवरी, 2023 को अभिगम्य।

[6] इंगिन नाइंग, "अनसर्टेन्टी श्राउड्स म्यांमार इलेक्शन", *वॉयस ऑफ अमेरिका, 24 जनवरी, 2023,*

https://www.voanews.com/a/uncertainty-over-elections-in-myanmar/6932184.html, 30 जनवरी, 2023 को अभिगम्य।

[7] एली मेक्सलर, "कैसे एक असफल लोकतंत्र विद्रोह ने म्यांमार के भविष्य के लिए मंच तैयार किया", *समय*, 8 अगस्त, 2018,https://time.com/5360637/myanmar-8888-uprising-30-anniversary-democracy/, 11 जनवरी, 2023 को अभिगम्य।

[8] "म्यांमार ने 2023 के अंत तक संघर्ष विराम की अवधि बढ़ाई", *सिन्हुआ,* 1 *जनवरी*, 2023, https://english.news.cn/asiapacific/20230101/12fede1a9b8a42b384ca4c787f0b18f0/c.html, 5 जनवरी, 2023 को अभिगम्य।

[9] खिन लिन क्याव, "म्यांमार जुंटा ने राजनीतिक दलों के लिए कठिन नियमों के साथ चुनाव की योजना बनाई", *ब्लूमबर्ग,* 27 जनवरी, 2023, https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-26/myanmar-election-junta-plans-poll-with-strict-rules-for-political-parties?leadSource=uverify%20wall, 30 जनवरी, 2023 को अभिगम्य।

[10] *"म्यांमार जुंटा के नियोजित 2023 आम चुनाव पर", इरावडी, 13 जनवरी, 2023* https://www.irrawaddy.com/opinion/analysis/on-myanmar-juntas-planned-2023-general-election.html, 15 जनवरी, 2023.